भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5694

जिसका उत्तर दिनांक 06.04.2022 को दिया जाना है

लोगों का पुनर्वास

5694. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा तेलंगाना में लांबापुर-पेद्दागट्टू क्षेत्र के भूजल में यूरेनियम संदूषण का उच्च स्तर पाए जाने के बाद सरकार ने उक्त क्षेत्र के 8 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कृष्णा नदी के जल को प्रभावित कर सकने वाले भूजल को और अधिक प्रदूषण से बचाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), खनन कार्य शुरू करने से पहले यूरेनियम निक्षेपों के आस-पास भूजल नमूनों सहित पर्यावरणीय आधाररेखा डाटा एकत्रित करता है ।

लम्बापुर-पेद्दागट्टू क्षेत्र, नालगोंडा जिला, तेलंगाना के आस-पास पर्यावरणीय आधाररेखा डाटा एकत्रीकरण के भाग के रूप में, एएमडी ने नवंबर 2018 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान 25 प्राइवेट नलकूपों / हस्तचालित पम्पों से भूजल नमूने एकत्रित किए हैं ।

25 नमूनों में से, चार नमूनें घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हस्तचालित पम्पों से और शेष 21 नमूने सिंचाई उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नलकूपों से लिए गए हैं । चार

हस्तचालित पम्प नमूने के स्थानों (जिससे जल घरेलू उद्‌देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है) में यूरेनियम का मूल्य 6 से 48 पीपीबी यूरेनियम की श्रेणी में है जो परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्‌वारा निर्धारित संरक्षा सीमा (60 पीपीबी) के नीचे है । शेष जल नमूनों में यूरेनियम मूल्य 1 से 2,618 पीपीबी तक भिन्न-भिन्न है । पच्चीस नमूनों में से तेरह में यूरेनियम की मात्रा 60 पीपीबी से कम है ।

यूरेनियम की उच्च मात्रा वाले अधिकांशतः नमूनों के स्थान खेती वाली भूमि में आते हैं जहां पर जल का उपयोग सिंचाई उद्‌देश्यों के लिए किया जाता है । ग्रेनाइटिक देश की चट्‌टानों के भूजल में यूरेनियम की उच्च मात्रा, इस प्रकार के भू-भागों में पाया जाना आम बात है । डाटा तेलंगाना सरकार के साथ साझा किया गया है ।

*****